O.I.H

भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं-1923

15/12/2021 को उत्तरार्थ

विषयः प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां

1923. श्री रेवती रमन सिंह:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में एक नई सहकारिता नीति लाने का विचार रखती है;
(ख) वर्तमान में देश में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिये पीएसीएस की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): देश में पहले से ही एक समृद्ध सहकारी विरासत और एक मजबूत सहकारी क्षेत्र है। हालाँकि, किसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक नीति एक गतिशील दस्तावेज है जिसे समय और स्थिति की जरूरतों के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है। सहकारिता मंत्रालय ने तदनुसार एक नई सहकारी नीति विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नाबार्ड और देश भर के प्रमुख सहकारी संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श शुरू किया है ताकि इस क्षेत्र को और मजबूत किया जा सके।

(ख) से (घ): वर्तमान में देश में लगभग 95 हजार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसीएस) हैं। हालांकि, सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश में देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करना शामिल है ताकि असेवित क्षेत्रों को भी कवर किया जा सके।

*****